आरबीआई गुवाहाटी ने की री-केवाईसी अभियान की प्रगति की समीक्षा

गुवाहाटी, 6 अगस्त (ख.सं.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय समावेशन के लिए चल रहे तीन महीने के राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान के अनुरूप असम भर में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे री-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक सुष्मिता फुकन ने की और इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उप महाप्रबंधक तथा असम के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक अमित रंजन के साथ-साथ आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों ने भाग लिया। यह बैठक वित्तीय सेवा विभाग के चल रहे अभियान (जुलाई-सितंबर) की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बैंकिंग सुविधा से वंचित नागरिक को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। समीक्षा के दौरान मुख्य चर्चाओं में लंबित री-केवाईसी मामलों की स्थिति, अब तक की प्रगति और शीघ्र पूरा करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय निदेशक ने अभियान की दक्षता में बाधा डालने वाली कई परिचालन बाधाओं की ओर ध्यान दिलाया और बैंकों से समन्वित प्रयासों से इन बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया। बैंकों को एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने, री-केवाईसी शिविर आयोजित करने और तेज व आसान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस करिस्पोंडेंट (बीसी) और ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाने का निर्देश दिया गया। बैठक का समापन सभी बैंकों से समय पर सटीक डेटा प्रस्तुत करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर री-केवाईसी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने की दिशा में गति बनाये रखने के लिए कार्रवाई करने के एक सशक्त आह्वान के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि योजना में हाई स्कूल के प्रथम और द्वितीय वर्ष, स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर के प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। अगले वर्ष स्नातक के अंतिम वर्ष की छात्राओं को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा, जिससे इस योजना के अंतर्गत छात्राओं का शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके बाद योजना में 10 लाख छात्राओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो माता-पिता अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए योजना आशा और प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। अब राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अरुणोदय और निजुत मोहना जैसी योजनाओं से सभी जातियों, जनजातियों और धर्मों के छात्रों को लाभ मिल रहा है। सरकार छात्रों के लिए अवसरों और उज्ज्वल भविष्य के द्वार खोलने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या ने छात्रों के लिए अवसरों को व्यापक बनाया है, जिससे वे बिना किसी बाधा के विविध शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने बाल विवाह के विरुद्ध अपने अभियान को नए सिरे से शुरू किया है। योजना 2.0 के शुभारंभ से चार लाख छात्राएं बाल विवाह के अभिशाप से खुद को बचा सकेंगी और साथ ही शैक्षणिक रूप से सशक्त होने के अपने सपने को भी साकार कर सकेंगी। हम 2026 तक बाल विवाह को शून्य पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार वितरित किए गए आवेदनों को संस्थानों में जमा किया जाना चाहिए और डेटा को एसएसीएआरटी, दर्पण और समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगु, गौहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नंनी गोपाल महंत, स्कूल एवं उच्च शिक्षा सचिव नारायण कुंवर और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा राज्य भर से कई मंत्री, विधायक, प्रधानाचार्य और छात्र भी गौहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।